MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Naresh Chandra Agrawal. ..*(Interruptions)*..

SHRI BALBIR PUNJ (Odisha): Sir, this is a very serious issue. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It's okay. He has mentioned this. ..*(Interruptions)*.. It is very serious that is why we admitted it in Zero Hour. ...*(Interruptions)*... Because of its seriousness only, it has been admitted. ..*(Interruptions)*..

DR. CHANDAN MITRA (Madhya Pradesh): Sir, the issue is very serious. ...*(Interruptions)*...

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश) सर, एक संगठन, जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ था ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : अब हो गया है, इसीलिए उनको बोलने दिया था ...(**व्यवधान**)...

श्री विक्रम वर्मा : मंत्री महोदय इसका जवाब दें ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : देखिए, आपको मालूम है कि ज़ीरो आवर में we cannot ask the Government to respond. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam) : Sir, Zero Hour is not the time to raise all this. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, no, whatever it is ...*(Interruptions)*...

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, the Assam Government is being ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : मि. पुंज, प्लीज़, आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, बैठिए ...(**व्यवधान**)...

Alleged scam in subsidy of fertilizers

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं अपने इस नोटिस के माध्यम से फर्टिलाइज़र्स विभाग द्वारा जो करीब 20,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है, उसे रखना चाहता हूं।

श्रीमन्, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जेना जी पिछली बार सदन में कह रहे थे कि प्रतिवर्ष हम एक लाख करोड़ रुपये फर्टिलाइज़र पर, चाहे एमएसपी का हो या पीएमके का हो, सब्सिडी के रूप में देते हैं। उस समय मंत्रालय को Maximum Retail Price फिक्स करने का अधिकार था। बाद में मंत्रालय ने इसके साथ एक नया शब्द जोड़ दिया - 'New Trend Based Subsidy'. इन शब्दों को जोड़ने के बाद एक तरफ उन्होंने तमाम खाद कंपनियों, चाहे IFFCO हो, IPL हो, Birla हो, Zuari Agro Chemical Ltd. हो, को सब्सिडी दी, दूसरी तरफ maximum retail price फिक्स करने का सरकार का जो अधिकार था, उसको वापिस ले लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि इस सत्र में किसानों को डीएपी, एनपीके इन सबकी बोरी पर करीब 400 से 500 रुपये ज्यादा देने पड़े।

श्रीमन्, यह बहुत गंभीर बात है। यह सरकार का अपना राइट था और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को चाहिए था कि वह maximum retail price को अपने पास रखता। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक काम और किया कि उन कंपनियों को विदेश में आउटलेट खोलने की परमिशन भी दे दी। अगर इन कंपनियों ने वहां से खाद को 600 डॉलर में खरीदा, तो हिन्दुस्तान में उसी खाद को 700 डॉलर में सप्लाई कर दिया। इस माध्यम से करीब 5000 करोड़ रपये का घोटाला किया गया। इस प्रकार सिर्फ 'New Trend Based Subsidy' शब्द डाल

कर करीब 15,000 करोड़ रुपये का मुनाफा उन कंपनियों को कराया गया। इसमें सबकी सोची समझी साजिश थी।

श्रीमन्, इस के बाद एक बात और सामने आई। यूरिया इम्पोर्ट करने का अधिकार सिर्फ STC और MMTC को था। भारत सरकार के उपक्रमों के तहत सिर्फ यही कंपनीज़ इम्पोर्ट कर सकती थीं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस पॉलिसी को तोड़ कर अपने एक मित्र, Coromondel Fertilisers Limited, जो मद्रास की एक कंपनी है, को डायरेक्ट लाइसेंस दे दिया कि वे सीधे यूरिया इम्पोर्ट कर सकते हैं। आखिर इस पॉलिसी को क्यों तोड़ा गया? इसके माध्यम से उस कंपनी ने इस वर्ष यूरिया इम्पोर्ट करने में करीब 5000 करोड़ रुपया पैदा किया। यह एक गंभीर बात है।

श्रीमन्, पूरे देश में किसानों को लेकर चिन्ता है। यहां भी किसानों को लेकर चिन्ता थी कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कल पूरा हाउस भी इसी बात के लिए चिन्ताग्रस्त था और जिस दिन सदन उठा, उस दिन भी यही चिन्ता थी। दूसरी तरफ मंत्रालय इस तरीके की छूट देकर करीब 20,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने की परमिशन दे रहा है। प्रधान मंत्री का कार्यालय इस पर चुप है, वित्त मंत्री का कार्यालय भी इस पर चुप है और फर्टिलाइज़र मंत्री का कार्यालय अपना काम करता रहा है।

श्रीमन्, मैंने यह एक गंभीर मुद्दा उठाया है और मैं चाहता हूं कि इसे स्वीकार करके सदन में चर्चा कराई जाए और मंत्री जी यहां पर खुद इसका जवाब दें।

श्रीमन्, घोटालों की सरकार पर रोज़ाना नये घोटालों के आरोप लगते जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर इस सरकार ने सही जवाब नहीं दिया, तो जनता के बीच एक बड़ा असंतोष पैदा हो जाएगा।

श्री बलवीर पुंज (ओडिशा): सर, मैं इनके साथ स्वयं को एसोसिएट करता हूं।

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी इनके साथ स्वयं को एसोसिएट करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Moinul Hassan. *(Interruptions)* ठीक है, all are associating; please note it down.

श्री विनय कटियार (उत्तर प्रदेश) : महोदय, आपने घोटालों, की चर्चा की, लेकिन किसानों को खाद तक नहीं मिल रही है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : कल किसानों के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है, आप नहीं थे ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... नहीं-नहीं, अगर आप कल आते तो आपको भी बोलने का मौका दिया जाता ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... देखिए, दूसरों का टाइम मत लीजिए ...(**व्यवधान**)... इस पर जिस तरह से सवाल उठाना चाहिए, वैसे उठाइए ...(**व्यवधान**)...

Missing of Haj Pilgrims in Mecca

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, everybody knows that every year, lakhs of people go to the Holy City of Mecca to perform Haj, one of the religious duties of the Muslims. This year also, it happened. The Government of India, the All India Haj Committee, the State Haj Committees and other private operators operate the entire system. I have raised this issue repeatedly in this august House that every year, we have been seeing the mismanagement taking place in arranging the matter.